नईदुनिया

संपादकीय

महंगाई पर काबू पाना कठिन

सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कई वर्ष से प्रयास कर रही है, मगर इसमें स्थिरता नहीं आ पा रही। रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई पांच फीसद के नीचे रखने की मंशा से कई बार बैंक दरों में बढ़ोतरी की और अभी तक वह उनमें कटौती करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा। खुदरा महंगाई पिछले महीने बढ़ कर 7.74 फीसद पर पहुंच गई। अब थोक महंगाई अपने तेरह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पिछले महीने यह 1.26 फीसद दर्ज हुई। पिछले वर्ष मार्च में यह 1.41 फीसद थी। थोक महंगाई पिछले दो महीने से लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि अप्रैल महीने में खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पाद विनिर्माण और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से थोक महंगाई बढ़ी है।

इस स्थिति में कब तक सुधार की संभावना है, इसे लेकर कोई आकलन पेश नहीं किया गया है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में कब नरमी दर्ज होगी, कहना मुश्किल है। विश्व में जिस तरह संघर्ष की स्थितियां और मंदी का दौर है, उसमें कीमतों में कमी को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता। विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में महंगाई बढ़ने की वजहें भी साफ हैं। कोयला उत्पादन क्षेत्र में विकास दर सुस्त बनी हुई है। कोयला आयात बढ़ा है। ऐसे में बिजली उत्पादन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। विनिर्माण में लागत पर खुदरा महंगाई का भी असर होता है। कोयला और बिजली की कीमतें बढ़ने से भी इस क्षेत्र में महंगाई बढ़ती है। इससे जाहिर है कि अभी आने वाले समय में जल्दी इस स्थिति में किसी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

महंगाई का एक बड़ा कारण विकास दर में असंतुलन भी है। कुछ क्षेत्रों में विकास दर काफी ऊंची है, तो कुछ में नीचे का रुख बना हुआ है। थोक महंगाई बढ़ने का अर्थ है कि खुदरा महंगाई पर उसका सीधा असर पड़ेगा। अगर वस्तुओं के उत्पादन पर लागत बढ़ेगी, तो खुदरा वस्तुओं की कीमतें उसके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ी हुई दर्ज होंगी। फिर, चूंकि महंगाई का आकलन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, वास्तविक महंगाई उससे कहीं अधिक होती है। इसीलिए अक्सर जब सरकारी आंकड़ों में महंगाई का स्तर घटा हुआ दर्ज होता है, तब भी आम उपभोक्ता कोई राहत महसूस नहीं करता। आम चुनाव की सरगर्मी में विपक्षी दलों ने महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है। इसलिए थोक महंगाई के ताजा आंकड़े एक बार फिर उन्हें सत्तापक्ष की आलोचना का अवसर देंगे। यह एक अजीब तरह का असंतुलन है कि देश की अर्थव्यवस्था का रुख ऊपर की तरफ है, जबकि महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसकी कुछ वजहें साफ हैं। महंगाई को सहनशील स्तर पर लाने के लिए जरूरी है कि बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़े, मगर बेरोजगारी बढ़ने, प्रति व्यक्ति आय घटने और क्रयशक्ति छीजती जाने की वजह से बाजार में संतुलन नहीं बन पा रहा। जिस मौसम में नई फसल की आवक तेज होती है, उसमें भी खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें ऊंची रहती हैं। दूसरी तरफ किसान फसलों की वाजिब कीमत न मिल पाने से परेशान दिखते हैं। जब तक अर्थव्यवस्था में कायम असंतुलन दूर करने का प्रयास नहीं होता, महंगाई पर काबू पाना कठिन ही बना रहेगा।

प्रधानमंत्री के रोड शो और सामाजिक समरसता

दृष्टिकोण

-मृत्युंजय दीक्षित

भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो में सामाजिक समरसता का अनूठा दर्शन हो रहा है। वह वाराणसी से तीसरी बार उम्मीदवार हैं। परचा भरने से एक दिन पहले वाराणसी में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। रोड शो में उमड़ा जनसमुद्र काशी के चुनावी इतिहास में अद्भुत व अकल्पनीय रहा। वाराणसी के पूर्व ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक के रोड शो में जिस प्रकार की जन भावनाएं मोदी के प्रति देखने को मिलीं, उनसे साफ संकेत मिलता है कि अबकी बार फिर मोदी सरकार ही बनने जा रही है । प्रधानमंत्री के रोड शो की सबसे बड़ी विशेषता सामाजिक समरसता है। इनमें नारी शक्ति का वंदन भी हो रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उनके समाजसेवा व भक्ति भाव के विविध रूपों के दर्शन भी हो रहे हैं। रोड शो के दौरान वह भीड़ में भी बच्चों को भी दुलार कर संदेश दे रहे हैं कि यह कल के निर्माता हैं।

जहां कहीं भी प्रधानमंत्री का रोड शो होता है वहां से नया समीकरण सामने आ जाता है और विपक्ष हतप्रभ रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। जब पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो निकल रहा था, उस समय उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और लोगों के आश्चर्यचकित होने का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब उन्होंने नीतीश कुमार के हाथ में कमल का फूल देखा अर्थात पटना के रोड शो में बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ में उनकी अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न न होकर कमल का फूल था जिसे लेकर अब बिहार की राजनीति में तरह-तरह के कयास लगने आरम्भ हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार का राजनीति किधर जाती है, नीतीश कुमार यह इशारा काफी है।

वाराणसी का रोड शो तो स्वाभाविक रूप से ही अद्भुत होना ही था। यहां मां गंगा के बेटे का रोड शो जो था। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए और उन्हें देखने के लिए हर कोई बेताब था । अपने सांसद के लिए पूरा बनारसी जनसमुद्र उमड़ पड़ा। स्वागत में झांकियां सजायीं गईं। पुष्प वर्षा की गई। भगवा और तिरंगे लहराये। हर-हर महादेव और जय श्रीराम से आसमान गुंजायमान कर दिया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सनातन का सूर्योदय हो चुका है बस उसका तिलक ही शेष रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पांच किलोमीटर लंबे रोड शो के माध्यम से सामाजिक, आध्यात्मिक व जातीय गुणा -गणित पूरी तरह से साध लिया है। वाराणसी की धरती पर यह लहर नहीं, सुनामी का आगाज है।

प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय राजग गठबंधन के सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति रही। उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्वोतर राज्यों के सभी बड़े नेताओं का संगम दिखा। इनमें उल्लेखनीय रही बिहार की चर्चित चाचा-भतीजे की जोड़ी अर्थात चिराग पासवान व पशुपति पारस की उपस्थिति। वाराणसी में दोनों की उपस्थिति व आपसी केमेस्ट्री को देखकर बिहार की सियासत में विरोधी दलों के नेताओं को तनाव हो गया है। चाचा भतीजे की इस जोड़ी को लेकर मोदी विरोधी मीडिया में जो कयास लगाये जा रहे थे वे ध्वस्त हो गए। वाराणसी में राजग नेताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से अपने नेता के साथ खड़ा है और उन्हें ही 400 पार सीटों के साथ तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इंडी गठबंधन पूरी तरह से फ्यूज है। उसके पास न तो नेता है और न ही विचार। न ही विकास का कोई रोडमैप।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चार प्रस्तावकों के माध्यम से भी सबका साथ का परिचय दिया। राम मंदिर का शुभ मुहूर्त में उद्घाटन करने वाले ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री, ओबीसी समाज के बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा तथा दलित समाज के संजय सोनकर उनके प्रस्तावक हैं। वाराणसी में परचा दाखिल करने से पहले नरेन्द्र मोदी ने भावुक कर देने वाला वीडियो भी जारी किया और मां गंगा के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। देश ने ही हमें 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा है।

अब वाराणसी पूरे देश की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन चुकी है। यहां से प्रधानमंत्री ने काशी व उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारत का समीकरण साधा है। देश के सभी महापुरुषों के कट आउट रोड शो में रहे। प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो के माध्यम से जहां देश के सामाजिक समीकरण के अंतर्गत जैन संन्यासी व शैव दक्षिण को समेटा वहीं दूसरी ओर वाराणसी के कोर वोटर 3 लाख ब्राह्मण मतदाता, 2.5 लाख से अधिक गैर यादव ओबीसी, 2 लाख कुर्मी, 2 लाख वैश्य, 1.5 लाख से अधिक भूमिहार और 1.5 लाख यादव सहित अनुसूचित जाति के मतदाताओं को भी साध लिया है।

प्रधानमंत्री मोदी किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते हैं और इस बार तो उनका नया रूप ही दिखाई पड़ रहा है। अभी तक यह कहा जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने नहीं आते। अबकी बार वह लगातार मीडिया को साक्षात्कार दे रहे हैं, वह चाहे छोटा हो या फिर बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री मोदी अपने साक्षात्कारों के माध्यम से मनौवैज्ञानिक रूप से विरोधी दलों का मनोबल तीव्रता के साथ ध्वस्त कर रहे हैं। विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में भी मोदी आगे निकल चुके हैं और विपक्ष के सारे नैरेटिव विफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से बार -बार कह रहे हैं कि अबकी बार 400 पार का नारा एक नारा भर नहीं है अपितु यह एक हकीकत बन चुका है, जिसे भारत की जनता ने करने का मन भी बना लिया है। हताश विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे पर लगातार तंज कसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में कभी किसी के घर गए हैं । बिहार के नेता प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो व साक्षात्कार आदि को एक इवेंट मात्र बता रहे हैं। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़े जनसमुद्र ने विरोधी दलों के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं।

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी

नजरिया

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों की ही भाषा में बात करें तो केरल में सबसे अधिक 59.79 प्रतिशत महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि सभी जगह पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिक अधिक हैं। दरअसल देखा जाए तो खेती और पशुपालन तो महिलाओं के भरोसे ही चल रहा है। शहरों में घरेलू कामकाज और रियल एस्टेट क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है।

असंगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति की बागडोर महिलाओं ने ही संभाल रखी है। देश की आर्थिक गतिविधियों के संचालन में असंगठित क्षेत्र की अपनी भूमिका है और इसमें कोई दोराय नहीं कि असंगठित क्षेत्र में श्रम शक्ति को भले ही मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता हो पर असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार के अवसर हैं। बहुत बड़े वर्ग की रोजी-रोटी असंगठित क्षेत्र पर ही टिकी हुई है। हालांकि असंगठित क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं।

इसमें रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नियमित आय का ना होना, स्वास्थ्य सुरक्षा सहित बहुत सी समस्याओं से दोचार होना पड़ता है। हालांकि सरकार असंगठित क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए समय-समय पर योजनाएं लाती है और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर उनकी वास्तविक संख्या व आवश्यक जानकारी जुटाते हुए योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता रहा है। खैर, बात भले ही थोड़ी अजीब लगे पर वास्तविकता तो यही है कि आज देश में असंगठित क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक हो गई है।

केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर देश में 29 करोड़ 56 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है जिसमें से महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। असंगठित क्षेत्र में आज महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी आधी से भी ज्यादा हो चुकी है। केन्द्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल की ही बात करें तो इसमें पंजीकृत 29 करोड़ 56 लाख श्रमिकों में से 53 फीसदी से भी अधिक महिला श्रमिक रजिस्टर्ड हैं जबकि पुरुष श्रमिकों की संख्या यही कोई 46 फीसदी से कुछ ही अधिक है। बात भले ही कुछ भी की जाती हो पर तस्वीर तो यही है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक श्रम कर रही हैं। भले ही व्हाइट कालर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम हो पर आज संगठित व असंगठित क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है।

भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल के आंकड़ों की ही भाषा में बात करें तो केरल में सबसे अधिक 59.79 प्रतिशत महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि सभी जगह पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिक अधिक हैं। दरअसल देखा जाए तो खेती और पशुपालन तो महिलाओं के भरोसे ही चल रहा है। शहरों में घरेलू कामकाज और रियल एस्टेट क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। करीब 15 करोड़ श्रमिक खेती-किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ साफ-साफ यह हुआ कि खेती-किसानी से आधे से भी अधिक श्रमिक जुड़े हुए हैं और इसमें भी कोई दोराय नहीं कि पुरातन काल से ही पशुपालन तो महिलाओं के भरोसे ही चलता आया है। खेती-किसानी में भी महिलाओं की प्रमुख भागीदारी होती है।

गली कूचे में बनिये की दुकान, चाय-पानी की स्टॉल या इसी तरह की किसी दुकान में काम करने वाले, चौकटियों में कारीगारी-बेलदारी के काम की प्रतीक्षा करने वाले, खेतों में जुताई, कटाई व इसी तरह के काम करने वाले, छोटे दस्तकारों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों, गली-मोहल्ले में घूमने वाले वेंडर्स और अस्थाई काम करने वाले लोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं। डेली वेजेज के आधार पर काम करने वाले लोगों को भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें महिला और पुरुष श्रमिक दोनों ही शामिल हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अपनी समस्या है। काम मिले तो मिल गया और नहीं मिला तो नहीं मिला। यानी असंगठित क्षेत्र में रोजगार व आय की स्थिरता नहीं होती। यही कारण है कि दूसरे दिन भी काम मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसके लिए रोजगार व आय की सुरक्षा व नियमितता की बात भी नहीं की जा सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की बात करना तो बेमानी होगी। मोटे रूप से रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य व आवश्यक सुविधाओं की सुलभता असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दूर की कोड़ी ही मानी जा सकती है। हालांकि असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर होने लगी है। पहली बात यह कि श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने से सरकार के सामने वास्तविक तस्वीर सामने आने लगी है। सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, श्रम योगी मान धन योजना, अटल पेंशन योजना और इसी तरह की अन्य योजनाओं से जोड़कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के प्रयास किए गए हैं।

अब देश-दुनिया में श्रमिक आंदोलन का समय तो करीब-करीब समाप्त ही हो चुका है। ऐसे में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैरसरकारी व सामाजिक संगठनों को आगे आते हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आवाज बनना होगा। अब तो चूंकि असंगठित क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिला श्रमिक अधिक हैं तो फिर और भी अधिक जिम्मेदारी हो जाती है। इसके साथ ही महिलाओं की समस्याओं को भी समझना होगा। सरकार को भी इस क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए फोकस करना ही होगा।

आजकल

सुशील मोदी का असामयिक निधन

करीब पचास वर्ष सुशील मोदी राजनीति में रहे। अलग-अलग समय में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों के लिए वे निर्वाचित हुए। उपमुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य राजनीतिक पदों पर रहते भी उनका व्यक्तित्व सदा बेदाग रहा। उन पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा।

बिहार में भाजपा का प्रमुख चेहरा थे। यह उनके मिलनसार, भरोसेमंद व्यक्तित्व और राजनीतिक कुशलता का ही नतीजा था कि बहुमत हासिल न कर पाने के बावजूद भाजपा बिहार में कई बार सत्ता में रही। सुशील मोदी की नीतीश कुमार से गहरी दोस्ती थी। हालांकि दोनों के दलों की वैचारिक पृष्ठभूमि अलग थी, पर सुशील मोदी पर नीतीश कुमार का भरोसा इतना दृढ़ था कि वे भाजपा के साथ गठबंधन करने को तैयार हुए।

यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल कर चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के बाद भी उन्होंने उसका साथ छोड़ा और भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। सुशील मोदी जयप्रकाश नारायण के प्रभाव में राजनीति में आए थे। फिर वे भाजपा के साथ हो गए और आजीवन उससे जुड़े रहे। वे प्रबुद्ध राजनीतिकों में से थे। हर वक्त देश-दुनिया की घटनाओं पर नजर रखते थे।

वित्तीय मामलों की उन्हें गहरी समझ थी। यही वजह है कि नीतीश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें वित्त मंत्रालय का भार भी सौंपा गया था। वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए। जिस समय जीएसटी की रूपरेखा तैयार हो रही थी, सुशील मोदी को राज्यों के वित्तमंत्रियों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। करीब पचास वर्ष वे राजनीति में रहे। अलग-अलग समय में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों सदनों के लिए वे निर्वाचित हुए। उपमुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य राजनीतिक पदों पर रहते भी उनका व्यक्तित्व सदा बेदाग रहा। उन पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मृदुभाषी थे। अपने विरोधियों के बारे में भी वे कभी तल्ख नहीं देखे गए। बहुत सोच-समझ कर और अर्थपूर्ण टिप्पणी करते थे। वे बिहार के लोकप्रिय नेताओं में थे। बिहार में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं, उसमें भाजपा को मजबूत स्थिति में खड़ा करने में सुशील मोदी का बड़ा योगदान था।

एड्स पर नियंत्रण, चिकित्सा तंत्र की बड़ी चुनौती...

डॉ. रमेश ठाकुर

विश्व एड्स वैक्सीन दिवस/18 मई/विशेष)

एड्स से निजात के लिए हमें सिर्फ सतर्कता और जागरुकता पर ही निर्भर नहीं होगा, इसके आगे भी सोचना पड़ेगा। आगे सोचने का मतलब, एड्स की वैक्सीन, दवा या टीके के अविष्कार की ओर कदम बढ़ना क्योंकि दिनों दिन ये लाइलाज बीमारी भयाभय रूप लेता जा रही है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में एचआईवी पॉजिटिव केस सामने आते हैं जिनमें हजारों की संख्या में मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये सच है, एड्स से डरावनी बीमारी शायद आज भी दूसरी कोई और नहीं जिसका मात्र नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती हैं। लोग भगवान से दुआ करते हैं, उन्हें कोई भी हारी-बीमारी क्यों न हो जाए, पर एड्स न हो

एड्स समाज की सबसे बड़ी कलंकित बीमारी है। कलंकित इसलिए क्योंकि इस बीमारी के चलते समाज में असमानता फैल रही है जो सभ्य समाज में कतई स्वीकार्य नहीं यही कारण है, एचआईवी लक्षण पता होने पर पॉजिटिव व्यक्ति से समाज एक तरह से नकार ही देता है। एड्स हो जाने के बाद समाज के अलावा सगे-संबंधी भी दूरी बना लेते हैं।

तब दुखी होकर पीड़ित एकांतवास जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। जबकि, देखा जाए तो एड्स की बीमारी मौत का तत्काल कारण नहीं बनती। एड्स रोगी लंबा जीवन जीते हैं। इसे स्वास्थ्य तंत्र की नाकामी कहें, या हुकूमतों की लापरवाही दशकों बीत जाने के बाद भी एड्स वायरस पर विजय प्राप्त नहीं हो सकी और न ही आजतक कोई मुकम्मल दवा या वैक्सीन बन सकी। एड्स से बचाव के लिए हम आज भी मात्र सतर्कता और जागरूकता पर ही निर्भर हैं, जो नाकाफी हैं। दरकार,अब वैक्सीन और दवा की है।

पहले के रिसर्च में यह तो तय हो चुका है कि एचआईवी एड्स की बीमारी जानलेवा है। चपेट में आने वाले मरीज की मौत होना निश्चित है। क्योंकि, एचआईवी के वायरस अपनी स्थित को बहुत तेजी के साथ बदलते हैं।

एचआईवी का वायरस मरीज के प्रतिरक्षा सिस्टम पर सीधा प्रहार करता है। वायरस अपनी मौजूदगी को नित बदलता रहता है। हिंदुस्तान के अलावा पूरे संसार की बात करें, तो एड्स पीड़ितों की संख्या इस समय लाखों-हजारों में नहीं, बल्कि करोड़ों-अरबों में हैं। पिंड छुड़ाने के लिए देश-विदेश की हुकूमत लाखों नाकाम कोशिशें करती हैं। हालांकि रिसर्च-औषधियों के शोध लगातार जारी हैं। पर, सफलता हाथ नहीं लग रही। कई मुल्क इस वैक्सीन पर शोध कर रहे हैं। हां, इतना जरूर है, 'इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव और द स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीच्यूट' ने इतनी सफलता जरूर हासिल कर ली है कि एचआईवी संक्रमितों की मरने-जीने की स्टेज बता सकती है।

वैसे, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एड्स भी मात्र एक वायरस ही है। लोगों में भ्रम है कि एड्स छूने से, साथ खाने से या हाथ मिलाने से फैलता है। जबकि, यह कोरा मिथक है। एड्स इनमें से किसी भी कारण से नहीं फैलता। साथ ही यह एक ही टॉयलेट प्रयोग करने से, छींकने या खांसने या फिर गले मिलने से भी नहीं फैलता। एड्स के फैलने के दूसरे कारण होते हैं। जैसे, संक्रमित खून चढ़ाना, एचआईवी पॉजिटिव महिला या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना, साथ ही एक से अधिक पार्टनरों के साथ सेक्स करना आदि मुख्य कारण हैं। इस बीमारी का जबसे पता चला है, तभी से संक्रमितों की संख्या में कमी के बजाय बढ़ोतरी हुई है। आज पूरे संसार में 'विश्व एड्स वैक्सीन दिवस' मनाया जा रहा है। जो एचआईवी वैक्सीन जागरुकता के लिए निर्धारित है जिसकी बहुत जरूरत है।

बहरहाल, बढ़ते संक्रमित मामलों को देखते हुए दरकार इसी बात की है कि एचआईवी वैक्सीन की तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जाए। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एचआईवी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया था जिसमें जानवरों का प्रयोग किया था। तब बताया गया था कि एचआईवी वायरस की प्रतिरक्षा के लिए जानवरों के रक्त एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिनके जरिए एचआईवी को रोका जा सकता है। हालांकि उनके इस दावे पर डब्ल्यूएचओ ने सवाल खड़े किए। मामला ज्यादा तूल पकड़ा तो फिर बात आगे नहीं बढ़ी। केंद्र सरकार ने सन-2030 तक एड्स के मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए लक्ष्य बनाया है।

वहीं, एड्स कंट्रोल सोसायटी के अनुसार कोरोना वायरस की भांति जरूरी चिकित्सीय व्यवस्था का प्रबंध बनाया है। अगर ऐसा होता है तो काबिलेतारीफ होगा, बड़ी सफलताओं में गिना जाएगा। लेकिन, ऐसे में सवाल उठता है, क्या अगले 6 साल में सरकार ये लक्ष्य पूरा कर पाएगी हिंदुस्तान में प्रति वर्ष अस्सी से नब्बे हजार केस सामने आते हैं। पिछले साल 2021 में 87,500 एचआईवी के मामले दर्ज हुए। वहीं, बीते तीन साल में 69,000 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र और दिल्ली से प्रति वर्ष 3 से 4 हजार के बीच नए केस आते हैं। इन दो राज्यों में संक्रमितों की संख्या दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा है। रेड लाइट एरिया से इनमें बड़ी भूमिका निभाती हैं।